claims worth Rs. 22.08 crore including Governmenmt of India's 2/3rd liability of Rs. 14.72 crores.

खाद्यान्नों की वसूली

1419. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कितनी वसूली की गई है तथा इस वसूली के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या वसूल किये गये खाद्यान्नों को सुरक्षित गोदामों में पहुंचा दिया गया है अथवा लाखों मन खाद्यान्न खुले पड़े होने के कारण वर्षा से सड़ रहा है और यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितना-कितना खाद्यान्न सड़ रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब उत्तर प्रदेश आदि में वर्षा के कारण, गेहूं भीग गया था, यदि हां तो इस प्रकार से भीगे हुए कितने गेहूं की खरीद की गई है और उस गेहूं की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ; और

(घ) नये वितरण के लिये क्या प्रणाली अपनाई गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण संलग्न हैं **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गैर-मौसमी वर्षा होने के कारण गेहूं की फसल को कुछ क्षति पहुंची थी । इस क्षतिग्रस्त गेहूं को सरकारी एजेन्सियों द्वारा नहीं खरीदा जा सका था क्योंकि वह विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं था । भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किये गये गेहूं को सुरक्षित भंडारण केन्द्रों में पहुंचा दिया गया है तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा में खरीदे गये क्रमश: लगभग 60 लाख मीटरी टन और 17.78 हजार मीटरी टन गेहूं मई 1987 के पहले पखवाड़े में हुई वर्षा से प्रभावित हुआ था । वर्षा से प्रभावित गेहूं के इस स्टाक का वातन और उसे दुरूस्त कर दिया गया है और अनुमानत: केवल लगभग 272 मीटरी टन की मामूली मात्रा क्षतिग्रस्त हुई हैं

(घ) वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया गया है

विवरण

1986-87 की फसल से अनाजों की वसूली

31-7-1987 को स्थिति

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	खरीफ के मोटे अनाज	गेहूं
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	14.58	—	—
2. अरूणाचल प्रदेश	0.01	—	—
3. असम	0.13	—	—

1		2	3	4
4.	हरियाणा	6.79	—	22.32
5.	जम्मू और कश्मीर	0.25	—	—
6.	कर्नाटक	1.18	—	—
7.	मध्य प्रदेश	4.73	0.08	नगण्य
8.	महाराष्ट्र	नगण्य	0.08	—
9.	उड़ीसा	1.15	—	—
10.	पंजाब	43.27	—	43.79
11.	राजस्थान	0.20	—	0.62
12.	तमिलनाडु	8.71	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	10.27	—	11.47
14.	पश्चिम बंगाल	0.47	—	—
15.	चण्डीगढ़	0.07	—	—
16.	दिल्ली	—	—	नगण्य
17.	पाण्डिचेरी	0.10	—	—
	जोड़ (अखिल भारत)	91.19	0.16	78.20

Mineral Exploration Programme

1420. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of STEEL AND MINES, be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for mineral exploration programme in the country;

(b) what are the areas proposed for exploration;

(c) whether excavation work has taken up in some areas; and

(d) if so, what are the details and the progress made as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTEMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Mineral exploration is being carried out every year in different parts of the country by the Geological Survey of India, State Departments of Geology and Mining and Mineral Exploration Corporation Ltd., as per their annual programmes approved by the Government.

(b) Mineral exploration is being carried out in the States of Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Bihar, Himachal Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Haryana, Punjab, Jammum and Kashmir, Arunachal Pradesh and Gujarat. The important minerals that are being explored during 1986-87 are base metals, chromite, phosphorite, apatite, potash, gold, diamond, tin tungsten coal and lignite, etc.

(c) and (d). Excavation (exploitation) is being carried out by the exploiting agencies like Coal India Ltd., Hindustan Copper Ltd., Hindustan Zinc Ltd., SAIL, PPCL, MOIL, Bha-